



Neutral Citation No-2026:AHC:300

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5198 वर्ष 2025

सुरेंद्र कुमार और एक अन्य याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: चरण सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य-प्रतिपक्षियों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थायी अधिवक्ता, गांव सभा के अधिवक्ता और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. लंबे विचार-विमर्श के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने केवल प्रार्थना संख्या-2 पर दबाव डाला है, जिसे यहां उद्धृत किया गया है: -

"ii) प्रतिपक्षी संख्या-3 को धारा 42-का उत्तर प्रदेश चक्रबंदी/जोत समेकन अधिनियम के तहत केस संख्या-30 (सुरेंद्र कुमार और अन्य बनाम राज्य) में दायर याचिकाकर्ताओं के दिनांक 19.06.2025 के आवेदन पर निर्धारित अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जो प्रतिपक्षी संख्या-2 (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या-2) के समक्ष लंबित है।

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 42-ए के तहत आवेदन भू-राजस्व अभिलेखों में दिनांक 19.09.1987 के आदेश के कार्यान्वयन के लिए 19.06.2025 से लंबित है।



4. स्थायी अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है, यदि इस न्यायालय द्वारा कुछ निर्धारित अवधि के भीतर दिनांक 19.06.2025 के उपरोक्त आवेदन के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है।

5. इस विवेचन में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने के लिए कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा, इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रतिपक्षी संख्या-3, चकबंदी अधिकारी को निर्देश के साथ, जिसके समक्ष उपरोक्त आवेदन दिनांक 19.06.2025 (अनुलग्नक संख्या-2) का निपटान लंबित है, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से कानून के अनुसार, छह महीने की अवधि के भीतर, अधिमानतः इसे शीघ्रता से तय करने के लिए।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, वर्तमान आवेदन का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 5, 2026

विनय

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)